

कृषि और आदिवासी विकास को लेकर मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कांकेर में तीन जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली

किसानों को जैविक खेती, कोदो-कुटकी और उन्नत कृषि के लिए जागरूक करें: कृषि मंत्री श्री नेताम

आश्रम-छात्रावासों के बच्चों का भविष्य संवारना हम सबकी जिम्मेदारी

रायपुर। किसानों को जैविक खेती, कोदो-कुटकी और उन्नत कृषि के लिए जागरूक करें: कृषि मंत्री श्री नेताम प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज जिला कार्यालय कांकेर के सभागार में कांकेर, बालोद और धमतरी जिलों के कृषि एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति,

खाद-बीज वितरण एवं किसानों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा भी मौजूद थे।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को जैविक खेती, कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक एवं लाभकारी फसलों के लिए प्रेरित करें तथा उन्नत कृषि तकनीक के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि खाद एवं बीज का समय पर वितरण सुनिश्चित करते हुए योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से अंतिम छोर के किसान तक पहुंचे, यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने मुदा की सेहत को संरक्षित रखने हेतु रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और जैविक खादों के उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया। उद्यानिकी के क्षेत्र में मुनगा, ऑयल पाम,



मसाला फसलें और कोदो-कुटकी जैसी फसलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भी उन्होंने निर्देश दिए।

बैठक में संचालक कृषि एवं प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम श्री अजय कुमार अग्रवाल द्वारा तीनों जिलों में बीज एवं खाद की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की स्थिति की

जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कांकेर जिले में 38,869.35 क्विंटल धान बीज में से 34,756.60 क्विंटल का वितरण हो चुका है। यूरिया खाद 25,568.13 मीट्रिक टन में से 20,525.87 मीट्रिक टन वितरित किया गया है। डीएपी खाद 7,024.15 मीट्रिक टन में से 6,002.05 मीट्रिक टन तथा एनपीके 9,129.55 मीट्रिक टन में से 7,216.73 मीट्रिक टन

वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कांकेर जिले के 75,559 कृषक बीमित हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में 17,575 कृषकों का बीमा किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिले के 82,395 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

बैठक में आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री नेताम ने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में निवासरत बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सहायक आयुक्तों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण करें और प्रतिवेदन कलेक्टर को दें। मंत्री ने छात्रावासों में स्वच्छता, बिजली, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावासों में पौधरोपण भी कराए जाने के निर्देश दिए।

पांच आईएसएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (ट्रस) के पांच अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को अस्थायी रूप से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

जारी सूची के अनुसार सुश्री नम्रता जैन वर्तमान में जिला पंचायत सुकमा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं को अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है।

हेमंत रमेश नंदनवार वर्तमान में जिला पंचायत बीजापुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं अब जिला पंचायत महासमुंद में इसी पद पर सेवाएं देंगे।

मुकुंद ठाकुर वर्तमान में

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा किसान कल्याण विभाग में उप सचिव हैं। उन्हें जिला पंचायत सुकमा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में भेजा गया है।

सुश्री नम्रता चौबे वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरायपाली (महासमुंद) के पद पर कार्यरत हैं। अब उन्हें जिला पंचायत बीजापुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।

तथा प्रखर चंद्रकार वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर हैं। उन्हें जिला पंचायत गरियाबंद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम पर सचिव रजत कुमार द्वारा जारी किया गया है।

सफलता के लिए अभ्यर्थी लक्ष्य पर फोकस रहें : वित्त मंत्री चौधरी

कांकेर में ‘मावा मोदोल’ कोचिंग संस्थान का किया शुभारंभ

रायपुर। सफलता का कोई शॉर्टकट अथवा विकल्प नहीं होता, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी पूरे मनोयोग और अनुशासन के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ें। उक्त आशय के विचार आज कांकेर शहर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में नि:शुल्क कोचिंग संस्थान ‘मावा मोदोल’ के शुभारंभ अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी व्यक्त किए। उन्होंने इस अवसर पर सेंट्रल लाइब्रेरी को नालंदा परिसर की तर्ज पर विकसित करने के लिए आश्चस्त किया।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए कहा। उन्होंने प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बड़ी परीक्षाओं में वही सफल होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास करते हैं। संवाद के दौरान प्रतियोगी छात्र-छात्राओं गुलशन जैन,



स्नेहा सिन्हा और कुलेश्वर नंदीश्वर के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं की तैयारी के साथ सहगामी करियर विकल्प भी खुले रखने चाहिए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कड़ी मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि कांकेर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है केवल सही दिशा और साधनों की। इस अवसर पर श्री चौधरी ने सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन किया तथा

जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया। कार्यक्रम में विधायक श्री आशाराम नेताम एवं श्री विक्रमदेव उसेंडी सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी और छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं। गौरतलब है कि ‘मावा मोदोल’ कोचिंग संस्थान कांकेर जिला प्रशासन की विशेष पहल है, जिसके माध्यम से युवाओं को नि:शुल्क कोचिंग और कैरियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थान के पहले चरण में भानुप्रतापपुर में हार्डटेक कोचिंग, ई-क्लास और ई-लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी।

नारको को-ऑर्डिनेशन, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति एवं नवीन कानून क्रियान्वयन पर समन्वय बैठक

सड़क दुर्घटना रोकने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत : कलेक्टर

धमतरी । कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आज नारको को-ऑर्डिनेशन सेंटर, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्त भारत अभियान, तथा नवीन कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अंबिनाश मिश्रा ने की। बैठक में पिछले बैठक के बिंदुओं और सुझावों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर द्वय रीता यादव, इंदिरा देवहारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, डीएसपी सुश्री मीना साहू, मोनिका मरावी सहित जिले के एसडीएम संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। नवीन कानूनों के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई।कलेक्टर श्री मिश्रा ने नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर गहरी चिंता व्यक्त करते



हुए कहा कि युवाओं का भविष्य नशे की गिरफ्त में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा और ठोस कदम उठाए जाए।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रा ने पूर्व बैठक दिए गए दिशा-निर्देश में बताया कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफएक संगठित व समर्पित प्रयास किए गए है। अब तक नशे के कारोबार से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है तथा

मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। वाहनों पर चलानी कार्रवाई सहित हेलमेट, सीट बेल्ट बांधे बिना वाहन चालकों पर भी कार्रवाई कर जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बैठक में जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग और राजकीय सड़कों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों में होने

वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गहन विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर अंबिनाश मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा न केवल एक महत्वपूर्ण विषय है, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी लाकर अमूल्य जिंदगियों को बचाया जा सकता है। उन्होंने आमजनों की जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने पर बल दिया। वहीं जरूरत के अनुरूप ट्रेफिक सिग्नल और अन्य अधोसंरचना कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा ब्लैक स्पॉट चिह्नकित कर आवश्यक सुरक्षा उपाय, जैसे स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड आदि लगाए। सड़क सुरक्षा को लेकर स्पीड लिमिट बोर्ड, डिवाइडर तथा मस्ट लाइट की व्यवस्था करने की बात कही गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले के संभावित दुर्घटना क्षेत्रों को चिह्नकित कर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

दुर्ग। दुर्ग जिले में 30 जुलाई को दो ननों की गिरफ्तारी ने देशभर का ध्यान आकर्षित किया, खासकर उस दिन जब विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जा रहा था। यह दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समर्पित होता है, और इसी दौरान छत्तीसगढ़ में यह मामला सामने आने से गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

राज्य में मानव तस्करी एक लगातार बढ़ती हुई समस्या बन चुकी है, विशेषकर आदिवासी और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में। 2023 से लेकर फरवरी 2025 तक प्रदेश में मानव तस्करी के 39 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 66 पीड़ित शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बस्तर और बलरामपुर

जैसे सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी की घटनाएं अधिक होती हैं। इन इलाकों में रोजगार के सीमित अवसर और बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोग तस्करी के झांसे में आ जाते हैं। खासकर नाबालिग लड़कियां और महिलाएं तस्करी का आसान निशाना बन रही हैं, जिन्हें नौकरी का झांसा देकर दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, जहां वे जबरन श्रम, घरेलू कामकाज या यौन शोषण जैसी स्थितियों में फंसी पाई जाती हैं। इसके अलावा पलायन भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ से 63,000 से ज्यादा लोग काम की तलाश में अन्य राज्यों में जा चुके हैं। बलौदाबाजार जिला इस मामले में सबसे आगे है, जहां से करीब

13,200 लोग पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम और खैरागढ़-गंडई-छुईखदान जैसे जिलों से भी भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और मानव तस्करी रोधी इकाइयों की सतर्कता से कई पीड़ितों को बचाया गया है और तस्करी से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन तस्करी का नेटवर्क अब भी जमीनी स्तर पर सक्रिय है। गांव-गांव में एजेंट मौजूद हैं, जो भोले-भाले ग्रामीणों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य में मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

श्रमिक बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ

कक्षा 6वीं से 12वीं तक नि:शुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध

जशपुरनगर । श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु श्रम विभाग द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के पहले दो बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा छठवीं में प्रवेश दिलाकर बारहवीं तक की शिक्षा आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

जशपुर के श्रम पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ उन छात्र-छात्राओं को मिलेगा जो कक्षा पाँचवीं में अच्छे अंक प्राप्त कर मेरिट



के टॉप-10 में स्थान प्राप्त करेंगे और कोरम समितियों द्वारा चयनित किए जाएंगे। चयनित विद्यार्थियों को सभी प्रकार की शुल्क माफकरते हुए प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, गणवेश, पुस्तकें, छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा की जाएगी। योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक है कि श्रमिक का नाम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार

कल्याण मंडल में कम से कम एक वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो तथा बच्चा कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए पात्र हो। योजना केवल प्रथम दो बच्चों पर लागू होगी। आवेदन के साथ जीवन्त श्रमिक पंजीयन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, पूर्व कक्षा में उत्तीर्णता की अंकसूची, वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की टी.सी.

(केवल प्रवेश हेतु), जाति प्रमाण पत्र तथा छात्र व छात्रा का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन श्रमिक स्वयं श्रमेव जयते मोबाइल ऐप कर सकते हैं, जनपद पंचायत पर कार्यरत श्रम संसाधन केंद्र या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।



रायपुर, 30 जुलाई (आरएनएस)। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय, महानदी भवन में केरल एवं ओडिशा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद चलाकुडी से श्री बेनी बेहनन, कोड्रयम से श्री के. प्रह्रसिज जीर्ज, कोल्लम से श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, कोरापुट से श्री सतगिरि उल्का, और केरल विधानसभा सदस्य श्रीमती रोजी एम. जॉन शामिल थे।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से राज्य में हाल ही में चर्चा में आए धर्मांतरण प्रकरण की जानकारी

साझा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय और समरसता में विश्वास रखने वाला प्रदेश है, जहाँ सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्चस्त करते हुए कहा कि मामले की जांच न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। कानून स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की बेटीयों और नागरिक सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें।

तहसीलदार एवं भूअभिलेख अधीक्षकों की हड़ताल समाप्त होने के संभावना,तूता में दे रहे धरना

रायपुर। राज्य में राजस्व कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण भूमि का आबंटन व्यपवर्तन सहित अन्य काम लंबित हो गये है। राजस्व मंत्री कार्यालय के अनुसार आंदोलनरत तहसीलदारों से चर्चा चल रही है जिसके आज समाप्त होने की संभावना है।

राजस्व कर्मचारी संघ द्वारा मिली जानकारी के अनुसार तहसील नायब तहसीलदार एवं भूअभिलेख अधीक्षक इस समय अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गये है जिसके कारण इस समय तहसील कार्यालय सुने पड़ गये हैं। तहसील कार्यालय में भूमि का का नामांतरण बंटॉकर तथा व्यपवर्तन एवं ऋण पुस्तिका बनाए जाते हैं। जिसको लेकर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग परेशान हो रहे है। तहसील और एसडीएम कार्यालय में पेशी दर पेशी बढ़ाई जा रही है। जमीन का सीमांकन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

राजस्व कर्मचारी संघ के अंतर्गत राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारी ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। राजस्व



निरीक्षकों की पदोन्नति परीक्षा में हुई घोटालों को लेकर वे लोग नाराज है। पटवारियों के अनुसार बाढ़ सहित अन्य आपदा आने पर वे महत्वपूर्ण कार्य करते है लेकिन उनकी बेहतर उपेक्षा की जा रही है। राजस्व मंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक के पश्चात एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। ज्ञात रहे पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों ने मांग की है कि उन्हें भी विभागीय पदोन्नति में 50 प्रतिशत स्थान दिया जाए।

ननों की गिरफ्तारी असंवैधानिक, बजरंग दल को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया : वृंदा करात

रायपुर। नारायणपुर में चर्च की दो ननों की गिरफ्तारी मानव तस्करी एवं धर्मांतरण मामले को लेकर पुलिस द्वारा की गई है। यह गिरफ्तारी असंवैधानिक है। तीनों आदिवासी लड़कियां नर्सिंग ट्रेनिंग लेने के लिए अपनी मर्जी से बाहर जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समुदाय विशेष पर यह हमला पहली बार नहीं किया गया है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़

में धर्म स्थलों में तोड़फोड़ एवं आगजनी एवं हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। संगठनों द्वारा सांप्रदायिक माहौल बनाकर शांति को भंग किया जा रहा है। उक्त आरोप भाजपा सरकार एवं पुलिस प्रशासन पर माकपा की पूर्व सांसद वृंदा करात, ए.ए. रहीम सांसद माकपा, राधाकृष्णन सांसद माकपा, पीपी मुनीर सांसद माकपा, के. जोन्स सांसद एवं कांग्रेस केरल प्रभारी श्रीमती एनी राजा पूर्व सांसद भाकपा ने संयुक्त रूप से प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में लगाया। करात एवं एनी राजा ने पत्रकारवार्ता में कहा कि उनके सांसदों का दल नारायणपुर भी गया था। वहां पर तीनों लड़कियों में एक सुखमनी मंडावी से चर्चा करने पर उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा कमरे में बंदकर शारीरिक प्रताड़ना देकर उन पर ननों के खिलाफ जबरिया ले जाने का आरोप लगाया है। उक्त पूरी गतिविधियां करात के अनुसार प्रायोजित हैं। वृंदा करात ने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को भी ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री आज होंगे दिल्ली रवाना, कैबिनेट विस्तार की अटकलें फिर तेज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज दोपहर रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका कार्यक्रम दोपहर 2:55 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल, रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट (6४६-6313) द्वारा प्रस्थान का है। वे शाम 5:05 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली पहुंचेंगे और वहां से 5:20 बजे कार द्वारा छत्तीसगढ़ सदन के लिए रवाना होंगे। उनका आज रात्रि विश्राम छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातें प्रस्तावित हैं। सूत्रों के अनुसार, वे कुछ केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य से जुड़े विकास कार्यों, योजनाओं और निवेश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

साथ ही मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के साथ ही एक बार फिर राज्य में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।* लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की प्रतीक्षा की जा रही है और मुख्यमंत्री के हर दिल्ली दौरे को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि जल्द ही कुछ नए चेहरे सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के भीतर और बाहर इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर महिला से 3 लाख की ठगी
रायपुर, 30 जुलाई (आरएनएस)। शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर दो लोगों ने



महिला से 3 लाख रुपए ठग लिए। प्रार्थिया की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया दुर्गा साहू 42 वर्ष राजीव नगर राजनांदगांव की रहने वाली है। बताया जाता है कि आरोपी बैजनाथ साहू एवं राजेश्वरी साहू ने साहू कॉम्प्लेक्स टिकरापारा के पास प्रार्थिया से कहा कि शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हो कहते हुए झांसे में लिया और उससे 3 लाख रुपए ऍठ लिए। प्रार्थिया की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले संचालकों, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले नशेडि़यों के विरुद्ध की गई छापामार

बलौदाबाजार-भाटापारा। होटल, ढाबा, ठेला आदि में लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले संचालकों, अवैध रूप से चखना सेंटर का संचालन करने एवं सार्वजनिक स्थल पर बैठकर शराब पीने वाले आरोपियों के विरुद्ध की गई छापामार कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दिनांक 27.07.2025 को विशेष अभियान चलाकर शराब पीने, बैठने एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने वाले तथा सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले कुल 15 होटल, ढाबा, ठेला, चखना सेंटर संचालकों पर की गई कार्यवाही। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों, शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों एवं जुआ, सट्टा का संचालन करने वाले तथा अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपियों की धरपकड़ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.07.2025 को सायं क्षेत्र अंतर्गत शराब भट्ठी के पास अवैध रूप से चखना सेंटर का

संचालन करने वाले, सडक मार्ग के किनारे स्थित होटल, ढाबा, ठेला आदि में पीने, बैठने की सुविधा उपलब्ध करारकर अवैध रूप से शराब पिलाने वाले तथा सार्वजनिक स्थल पर बैठकर शराब पीने वाले कुल 15 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया है। पकड़े गए सभी 15 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत विधिवत कार्यवाही किया गया है।

- आरोपियों के नाम
- संतोष देवांगन उम्र 52 साल निवासी ग्राम खान थाना सिटी कोतवाली
 - किशन पनका उम्र 35 साल निवासी ग्राम करमदा थाना सिटी कोतवाली
 - लक्ष्मी वर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम करमदा थाना सिटी कोतवाली
 - विनोद वर्मा उम्र 52 साल निवासी ग्राम खान थाना सिटी कोतवाली
 - दुलार साहू उम्र 42 साल निवासी ग्राम करमदा थाना सिटी कोतवाली
 - भागवत वर्मा निवासी ग्राम जरौद थाना भाटापारा ग्रामीण

कोयला लेवी घोटाला : रायपुर जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी होंगे शिफ्ट, व्हीआईपी ट्रीटमेंट और सिंडिकेट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी घोटाले में फंसे आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी को रायपुर से अंबिकापुर जेल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। जेल प्रशासन ने विशेष ईडी कोर्ट में इस बाबत अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। जेल अधिकारियों का आरोप है कि सूर्यकांत जेल में अनुशासनहीनता कर रहे हैं और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे।

बताया गया है कि ईडी की विशेष अदालत में रायपुर जेल में बंद कोयला, आबकारी और कस्टम मिलिंग मामलों से जुड़े आरोपियों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। इन पर आरोप है कि ये आरोपी जेल के अंदर एक संगठित सिंडिकेट चला रहे थे और उन्हें विशेष सुविधाएं मिल रही थीं। इस मामले के उजागर होने के बाद रायपुर जेल प्रशासन ने सभी आरोपियों को राज्य की



अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (४४४) ने पीएमएलए अधिनियम 2002 के तहत कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य से जुड़ी 49.73 करोड़

रुपए की चल-अचल संपत्तियों को 30 जनवरी 2025 तक अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। इसमें बैंक खातों में जमा राशि, लग्जरी वाहन, नकदी, सोना-चांदी के आभूषण और जमीनें शामिल हैं। ये संपत्तियां न सिर्फ सूर्यकांत तिवारी की, बल्कि उनके

साथ अन्य आरोपियों की भी हैं।यह मामला छत्तीसगढ़ में कोयले के अवैध परिवहन और उस पर अवैध वसूली से जुड़ा है। ईडी की जांच के अनुसार, सरकारी संरक्षण में एक संगठित नेटवर्क तैयार कर कोयला कारोबारियों से प्रति टन लाखों की उगाही की जाती थी। यह पैसा बिचौलियों और रसूखदार अधिकारियों के माध्यम से सफेद किया जाता था। आरोप है कि यह अवैध कमाई राजनीतिक दलों की फंडिंग, महंगी संपत्तियों की खरीद और विलासितापूर्ण जीवनशैली में खर्च की गई।जांच में यह भी सामने आया है कि इस घोटाले में नौकरशाहों, कारोबारियों और कुछ नेताओं की संलिप्तता रही है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने अब तक करोड़ों की संपत्ति जब्त की है और कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।फैलिहाल सूर्यकांत त्रिपाठी को रायपुर जेल से हटाकर अंबिकापुर भेजने की प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के अनुसार सभी कांग्रेसजनों को लेकर चलने की बैठक
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा शीघ्र ही विभिन्न जिलों के अध्यक्ष एवं मंडलों की अध्यक्षों को बदले जाने का संकेत मिला है। इसी तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें प्रदेश प्रभारी शामिल हुए। मंडल कमेटी की गठन की महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कांटे अध्यक्ष उधोराम वर्मा के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ ,मंडल कमेटी का महत्वपूर्ण इसी बात से गंभीरता दिखती है कि प्रदेश सह प्रभारी स्वयं बैठक में उपस्थित होकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मशा अनुरूप बने सभी को साथ लेकर काम करने वाले को बनाने निर्देशित किए,रायपुर जिले के मंडल सृजन प्रभारी पूर्व मंत्री डॉ शिव डहरीया ने सभी ब्लॉकों एवं मंडल स्तर पर बैठक कर उदयपुर घोषणा अनुरूप 50प्रतिशत मंडल के पदाधिकारी स ज़रूर हज़ू क़ ह,महिला,अल्प संख्यक होना चाहिए साथ ही 50वर्कार्यकरणीय 50वर्ष से हो का छिए साथ ही समय सीमा में मंडल कमेटी गठन करने की बात कही।

कांवड़ यात्रा के बहाने राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे राजनेता 3 अगस्त को

मूणत बाबा बागेश्वर धाम के भक्त विकास उपाध्याय एवं कई सामाजिक संस्थाएं निकालेंगी कांवड़ यात्रा

यातायात की व्यवस्था चरमराने की आशंका

रायपुर। सावन में भगवान शिव की आराधना की जाती है लेकिन राजनेता अब कांवड़ यात्रा के बहाने अपने राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तीन अगस्त को पश्चिम के विधायक राजेश मूणत, बाबा बागेश्वर धाम के भक्त, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित अनेक पार्षद एवं सांसद भी कांवड़ यात्रा विभिन्न मार्गों से निकालेंगे जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।

मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री एवं पश्चिम के विधायक राजेश मूणत 3 अगस्त को गुडियारी हनुमान मंदिर के पास स्थित धर्मशाला से एक विशाल कांवड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अनेक स्थानों पर होर्डिंस एवं पाप्पलेट बांटे जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वालों के लिए भोजन नास्ते की उत्तम व्यवस्था की जा



रही है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले महिलाओं को पीली साड़ी कांवड़ एवं प्लास्टिक का लोटा दिया जा रहा है। पुरुषों को भगवा रंग की टी शर्ट बांटने का कार्यक्रम है। मूणत के वार्ड स्तर पर पार्षद अधिक से अधिक लोगों

को लाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद वार्ड के आनंद अग्रवाल चूड़ामणी वार्ड के दीपक जायसवाल वार्ड नंबर जोन 7 की अध्यक्ष श्वेता वर्मा सहित गुडियारी क्षेत्र के पार्षदों को भक्तों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई

एनआरआई शिखर सम्मेलन में शामिल होने अमरीका जाएंगे ओपी चौधरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज कैबिनेट बैठक के बाद अमेरिका रवाना होंगे। यात्रा में अमेरिका में बसे छत्तीसगढ़िया भाई-बहनों को मातृभूमि से जोड़ने, निवेश के अवसरों को प्रोत्साहित करने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रवासियों को विकासशील से विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेंगे और इस वर्ष छत्तीसगढ़ के प्रथम एनआरआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। वे विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ के विजन छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के बारे में भी जानकारी साझा करेंगे, जो 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप है।

वित्त मंत्री अमेरिका में पढ़ाई करने वाले छत्तीसगढ़ी युवाओं के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम विकसित करने और स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के अनुभवों पर चर्चा करेंगे।



वित्त मंत्री निवेशकों और उद्यमियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संयुक्त उद्यम की संभावनाओं पर भी बात करेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इसके अतिरिक्त, वे प्रवासी भाई-बहनों को छत्तीसगढ़ के आगामी रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। उनकी इस यात्रा में वे 7 दिन अमेरिका के प्रवास में रहेंगे।

युवा कांग्रेस की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित

रायपुर । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने युवा कांग्रेस की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के मोहम्मद शाहिद को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं पेंड्रा जिले की प्रीति

मांझी को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बनाया गया है। एआईसीसी से आदेश भी जारी किया गया है।युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मोहम्मद शाहिद नियुक्त किया गया है। सूची में 14 युवा चेहरों के नाम शामिल हैं। मोहम्मद शाहिद के अलावा अजय छिकारा, खुशबू मंगला शर्मा, लेनिन प्रसाद, मनीष चौधरी, मिर्तेन्द्र दर्शन सिंह, निगम भंडारी, शेष नारायण ओझा, शिवि चौहान, स्मृति लेका, श्रवण राव, सुरभि द्विवेदी, तारह जॉनी और विकास छिकारा का नाम शामिल है।

प्रीति मांझी को बनाया गया राष्ट्रीय संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले की प्रीति मांझी को भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रीति मांझी को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली में राहुल गांधी और प्रीति मांझी के बीच मुलाकात हुई थी।

त्योहारी सीजन में फुटपाथ पर ठेका गुमटी वालों को हटाने से गरीब परेशान

टाटीबंध के होटल सरोवर पोर्टिकों का आकस्मिक अभियान

कम्पोस्ट पीट नहीं मिला, सूखा और गीला कचरा पृथक नहीं किया जाना पाया गया

रायपुर । रायपुर नगर निगम द्वारा मालवीय रोड जीई रोड सहित अन्य स्थानों पर इस समय अवैध कब्जा हटाओ अभियान जारी है। टाटीबंध में अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं आमपारा से लेकर एम्स तक गुमटी ठेला वालों को हटाने से गरीबों में रोष है। नगर निगम द्वारा इस समय भरी बरसात और त्योहारी सीजन में अवैध कब्जा हटाने से कपड़ा, जूता, फल, साड़ी, बेचकर फुटपाथ पर अपना जीवन यावन करने वालों को काफी परेशानी हो रही है। छोटे व्यापारियों एवं गुमटी चालकों के अनुसार चिकनी मंदिर मालवीय रोड से लेकर आरएस शुक्ला मार्ग बैजनाथ पारा में एक्स्पीन

चौक तक रक्षाबंधन तीजा सहित अन्य प्रमुख त्योहार होने के कारण इस समय जमकर खरीददारी हो रही है। लेकिन निगम द्वारा निरंतर कब्जा हटाए जाने से ये लोग परेशान है। निगम आयुक्त विध्वदीप एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र में चलाये जा रहे टीम प्रहरी अभियान के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र के जोन 8 में टाटीबंध में स्थित होटल सरोवर पोर्टिको का आकस्मिक निरीक्षण निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता और जोन 8 नगर निवेश टीम, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल, निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह के दिशा निर्देशन में जोन स्वास्थ्य अधिकारी गोपीचंद देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल, उपअभियंता नगर निवेश विभाग लोचन चौहान, स्वच्छता निरीक्षक रितेश झा की उपस्थिति में किया गया।

संपादकीय

एफटीए भारत को देगा नया वैश्विक आयाम

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और चार देशों के यूरोपीय समूह ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आगामी एक अक्टूबर से लागू होगा। आइसलैंड, लिकटेस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड ईएफटीए के सदस्य देश हैं। इस समूह का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार स्विटजरलैंड है। बाकी के तीन देशों के साथ भारत का व्यापार बनिस्वत कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की



पल प्रति पल की कविता

शब्द भी सीधे सपाट बढ़ते जाते
रुकते नहीं,
नदिया भी निर्झरिणी की तरह बलखाती, लहराती,
खिलखिलाली बहती रुकती नहीं निर्बाध
बहती जाती
समंदर में समूचा विलीन होने तक,
कविता भी पल्लवित पुष्पित होती खंडकाव्य होने तक

पल प्रति पल की कविता
या कविता का प्रति पल
भी इसी तरह होते हैं।
मेरे घर की सीढ़ियाँ भी
ऊपर की जाती हैं
नीचे क्यों कर नहीं आती,
शब्द भी इसी तरह

कारोबारी मामलों में मानसिक अस्थिरता और हर छोटे-बड़े देश पर टैरिफ थोपने की आतुरता के चलते ईएफटीए के तहत मिलने वाली बाजार पहुंच निश्चित ही भारत के लिए उत्साहजनक घटनाक्रम है।

इस बाजार पेशकश में 100 फीसद गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ में रियायत शामिल हैं। समझौते में भारत 82.7 फीसद टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो ईएफटीए के 95.3 फीसद निर्यात को कवर करती है।



अंतरिक्ष में जाते
लौटकर नहीं आते,
कविता,दोहा,चौपाई
और छंद बनकर,
कविता का आज,
आज की कविता भी
इसी तरह की होती,
ऊपर जाती सीढ़ियां
संदेश बनकर फिर
लौटकर क्यों नहीं आती
कोई न कविता न सीढ़ियां,
बस अंतरिक्ष बन बहती जाती
मेरे विचारों की तरह।
संजीवनी बन कर।

- संजीव ठाकुर।

टैरिफ आर्थिक युद्ध नहीं, आत्मनिर्भर शांति का रास्ता बने



ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

? ललित गर्ग ?

जब किसी वैश्विक ताकत के शिखर पर बैठा नेता ‘व्यापार’ को भी ‘सौदेबाजी’ और ‘दबाव नीति’ का औज़ार बना ले, तब यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर देता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत सिद्धांतों को भी चुनौती देता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफलगाकर ऐसा ही एक आर्थिक आघात पहुँचाया है। इस टैरिफका लक्ष्य स्पष्ट है, भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को बाधित करना और अमेरिकी वर्चस्व की पुनः स्थापना करना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य एवं भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में अमेरिका की ‘ट्रंपीय’ दादागिरी, एवं टैरिफ का तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव कितना क्या असर दिखायेगी, यह भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इस सन्दर्भ में भारत सरकार की दृढ़ता सराहनीय है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, दोनों का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 190 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ट्रंप और मोदी ने इस आंकड़े को दोगुना से भी ज्यादा 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उस लक्ष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। ऐसे में, भारतीय कंपनियों को बहुत संभलकर अपने लिए नए बाजार खोजने व बढ़ाने चाहिए।

भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने भारत को उत्पादन और नवाचार का नया केंद्र बनाया है। भारत का टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेवा क्षेत्र वैश्विक बाजार में निरंतर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा टैरिफथोपना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा से उपजे भय का संकेत है। लेकिन यह निर्णय केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। ट्रंप प्रशासन हमेशा से ही व्यापार संतुलन के मुद्दे को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखता रहा है। ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति का मुख्य हथियार रहा है, दूसरों को पीछे धकेलकर अमेरिका को आगे लाना। यह एकतरफा सोच व्यापार के मूल्यों और साझेदारी की भावना को कमजोर करती है। व्यापार समझौते पर 1 अगस्त की समय सीमा तक दोनों देशों के बीच जारी बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंचने का बड़ा कारण भारत का अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होना रहा है। उसे आगे भी तैयार नहीं होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत अमेरिका से ऐसा व्यापार समझौता कर ले, जो केवल उसके हित में हो। इस तरह के समझौते तो तभी हो पाते हैं, जब दोनों पक्षों के हित सधते हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए और यह स्पष्ट करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुचित दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। भारत को ट्रंप के मनमाने फैसलों से डरने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं, क्योंकि वे अपने फैसलों से पीछे हटने और उन्हें पलटने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस रवैये के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत भी हो रही है। उन्हें यह



समझ आ जाए तो अच्छा कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है और अमेरिका का भी प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा।

डोनाल्ड ट्रंप की नीति अक्सर ‘दबाव डालो और झुकावो’ पर आधारित रही है। चीन, यूरोप, मैक्सिको के साथ भी ट्रंप की व्यापार नीति टकरावपूर्ण रही है। लेकिन भारत, ऐतिहासिक रूप से संतुलन साधने वाली कूटनीति में विश्वास करता रहा है। भारत ने कई बार वार्ता के माध्यम से समझौते की दिशा में पहल की, लेकिन ट्रंप की आक्रामक नीति और ‘डीलमेकिंग’ की व्यक्तिगत शैली ने किसी संतुलन को बनने नहीं दिया। भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत टैरिफन केवल आर्थिक रूप से अनुचित है, बल्कि यह उभरते राष्ट्रों के आत्मनिर्भर बनने के अधिकार का भी हनन है। यह नव-उपनिवेशवाद का नया रूप है, जहाँ आर्थिक हथियारों से शक्तिशाली राष्ट्र, विकासशील देशों को नियंत्रित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफबढ़ाने और जुर्माना लगाने की जो घोषणा की, वह उनकी दबाव की राजनीति का ही हिस्सा है। इस राजनीति की पोल खुल चुकी है। अच्छा होगा कि इसे देश के विपक्षी दल भी समझें। इसलिए और भी समझें कि संसद में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि सैन्य कार्रवाई को स्थगित किए जाने के सिलसिले में विश्व के किसी भी नेता की कहीं कोई भूमिका नहीं। स्पष्ट है कि भारत-पाकिस्तान के बीच कोई कार्रवाई को कथित तौर पर रोकने का ट्रंप का दावा फर्जी है। वास्तव में इसी कारण वे अपने इस थोथे दावे को बार-बार दोहरा रहे हैं।

आज का भारत न केवल एक विशाल बाज़ार है, बल्कि एक नवाचारशील शक्ति भी है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या, तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, और विविधता से समृद्ध उत्पादन क्षमता भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रही है। भारत अब ‘निर्भरता’ की नीति से निकलकर ‘आत्मनिर्भरता’ की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के टैरिफका प्रभाव सीमित और अस्थायी होगा, लेकिन भारत की आर्थिक विकास यात्रा दीर्घकालिक और दृढ़ है। भारत के लिए यह चुनौती अवसर में बदलने का समय है, नए बाजारों की तलाश, घरेलू उत्पादन को और सशक्त बनाना, और वैश्विक साझेदारियों को नए रूप में ढालना। ट्रंप की दादागिरी भारत को झुका नहीं सकती। बल्कि यह भारत को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे सकती है। यह समय है जब भारत को अपने उत्पादन, नवाचार, निर्यात और कूटनीति

को और धार देने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि शक्ति का उतर शक्ति से नहीं, दूरदृष्टि और नीति से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का टैरिफ एक चुनौती है, लेकिन भारत की आत्मा में संघर्ष से जीतने का इतिहास है। हमने हर संकट को अवसर में बदला है, और इस बार भी हम यही करेंगे, न केवल अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए भी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्थिक चिंतन मूलतः ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘विकास के साथ विश्वास’, और ‘समान साझेदारी’ के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। वे वैश्विक मंच पर भारत को एक समानाधिकार संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि किसी बड़े राष्ट्र की कृपा पर चलने वाली व्यवस्था के रूप में। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफका प्रहार करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सोच विरोध नहीं, विकल्प पर आधारित होती है। वे इस तरह के दबावों को एक नई दिशा में सोचने और घरेलू उत्पादन एवं वैश्विक विविधीकरण का अवसर मानते हैं। टैरिफवार के उतर में मोदी की प्रतिक्रिया सकारात्मक ही होती हुई दिख रही है, वे ट्रंप के टैरिफसे प्रभावित क्षेत्रों जैसे स्टील, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल को सरकारी सब्सिडी, टैक्स रियायत और तकनीकी समर्थन के जरिए बल दे सकते हैं। अमेरिका के अतिरिक्त यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाज़ारों में भारत अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए इस टैरिफ से उत्पन्न संकट को संतुलित कर सकता है।

ट्रंप भारत को अपना मित्र मानते हैं। लेकिन यह कैसी मित्रता है, जिसमें ट्रंप को भारत के गरीबों, किसानों, मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन मोदी की विदेश नीति में भी ‘अमेरिका के साथ मित्रता’ है, लेकिन ‘आत्मगौरव की कीमत पर नहीं’। वे संवाद और दृढ़ता-दोनों का प्रयोग करते हैं। दबाव की राजनीति से न तो भारत झुकेगा, न रुकेगा। ट्रंप का टैरिफहो या कोई और वैश्विक चुनौती, मोदी का भारत हर संकट में अवसर खोजता है। मोदी की आर्थिक दृष्टि एवं नीतियां किसी बाहरी राष्ट्र के मनोनुकूल नहीं, बल्कि भारत की आवश्यकताओं, संभावनाओं और स्वाभिमान के अनुरूप गढ़ी गई हैं। जब वैश्विक महाशक्तियां टैरिफके हथियार से डराने लगे, तो समझो कि भारत की प्रतिस्पर्धा ने उन्हें असहज कर दिया है। मोदी इसे चुनौती नहीं, पहचान मानते हैं। मोदी कहते हैं-‘लोकल को ग्लोबल बनाओ’, और यही उनका उत्तर है। हर टैरिफ हर दबाव, हर चुनौती को। मोदी की अर्थनीति उद्यमशीलता को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ती है। उनका आर्थिक चिंतन ‘केवल विकास’ नहीं, बल्कि स्वराज्य आधारित समावेशी आर्थिक स्वतंत्रता है। ट्रंप के टैरिफकी चुनौती को वे उसी तरह लेते हैं जैसे उन्होंने कोविड या ग्लोबल मंदी की ली थी-साहस, दूरदर्शिता और आत्मनिर्भरता के साथ। यह निजी विचार है।

अधिकांश देशों के लिए टेढ़ी खीर ट्रंप की टैरिफ रणनीति

प्रो. लल्लन प्रसाद

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ रणनीति ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर दिया है। आयात-निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी के ऊपर अमेरिका के साथ समझौता करना अधिकांश देशों के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। ट्रंप के लिए अमेरिका पहले बाकी सब बाद में। अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए उन्होंने जो बातें कही थी उन पर तेजी से अमल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि व्यापार, टैक्स, इमीग्रेशन और विदेशी मामलों में जो नीतियां अपनाई जाएंगी उसमें अमेरिका के लोगों के हित को प्राथमिकता दी जाएगी। अपने देशवासियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिका में बनी चीजे खरीदें और अमेरिकंस को नौकरी दें, अमेरिका को फिर से पहले की तरह, शक्तिशाली, संपन्न और गौरवशाली राष्ट्र बनाएं। अमेरिका का व्यापार घाटा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने टैरिफ नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा कर दी। अधिकांश देशों के साथ घाटे में व्यापार को रोकने के लिए आयात पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की जिसने अधिकांश राष्ट्रों को समझौते के टेबल पर बैठने को मजबूत कर दिया, इसमें छोटे और बड़े सभी राष्ट्र शामिल हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और छोटे राष्ट्रों ने उनकी बात आसानी से मान ली, किंतु विकसित और कई विकासशील देशों ने इसका का विरोध किया।

कुछ राष्ट्रों के साथ समझौता हो चुका है किंतु अभी बड़ी संख्या में ऐसे राष्ट्र हैं जो उनके द्वारा प्रस्तावित टैरिफ मानने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका में रह रहे प्रवासी नागरिक जो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा अपने देश में अपने परिवार के लोगों को भेज रहे थे; उस पर पहली बार टैक्स लगाया गया। अमेरिकी इमीग्रेशन नीति में व्यापक परिवर्तन किया गया। अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशियों की नियुक्ति पर अंकुश लगाए जा रहे हैं। कंपनियों से कहा जा रहा है कि वह दूसरे देशों में अपने प्लांट न लगाकर अमेरिका में ही उत्पादन करें। शुरू में उन्होंने जो टैरिफ रेट प्रस्तावित किए उनमें कंबोडिया, लॉओस, म्यांमार, बांग्लादेश, सर्बिया, थाईलैंड, बोस्निया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका को 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत एवं ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान और मलेशिया को 25 प्रतिशत से 29 प्रतिशत के ब्रैकेट में शामिल किया। न्यूनतम टैरिफ पहले 10 प्रतिशत रखा था बाद में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। टेढ़ी उंगली से घी निकालने की नीति अपनाई, पहले जो तारीख तय किया उससे कुछ देश उनके आगे झुक गए, फिर उन्होंने 1 अगस्त की तारीख दी है जिसके बाद भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अप्रैल 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने वादा किया था 90 दिन में 90 देशों के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन अब तक मात्र पांच देशों के साथ अमेरिका का टैरिफ समझौता हो सका जिसमें ब्रिटेन, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस शामिल हैं।

यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ अभी तक समझौता नहीं हो पाया, ट्रंप के ही शब्दों में उन देशों के साथ समझौते के 50-50 परसेंट चांस है। ब्रिक्स देशों पर ट्रंप ने 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की क्योंकि उनके अनुसार ये देश अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर को ट्रंप दुनिया के मुद्राओं का बादशाह मानते हैं और इसको चुनौती देने वाले सभी देशों के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे रहे रहे हैं। ब्राजील के ऊपर तो उन्होंने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने तक की धमकी दे दी है जिसका वहां के राष्ट्रपति ने विरोध किया है। बदले में अमेरिकी वस्तुओं पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की



बात की। बाहर से आयात होने वाली वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाने या प्रतिबंधित करने से बहुत से राष्ट्रों को भारी नुकसान की आशंका है जो उनके मुख्य उत्पाद हैं और जिनका अमेरिका में बड़ी मात्रा में अब तक आयात होता रहा है, जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लैडर प्रोडक्ट्स, जेम्स एवं ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स और व्हीकल्स आदि। जिन चीजों की अमेरिका में उनकी जरूरत से अधिक पैदावार है जैसे कृषि और डेयरी पदार्थ उनके लिए ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के और देश अपना बाजार अमेरिका के लिए पूरी तरह से खोल दें, भारत पर भी जिसके लिए दबाव डाल रहे हैं।

भारत के 33 अरब डॉलर के र प्रतिशत और आभूषण निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 30 प्रतिशत है। अमेरिका के जेनेरिक दवा आयत के 47 प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति भारत करता है। अमेरिका से भारत मुख्य रूप से खिनज ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर मशीनरी और विद्युत मशीनरी के अलावा चिकित्सा उपकरण, धातुएं सिक्रे, वस्त्र और लोहे, इस्पात और अल्युमिनियम की वस्तुएं भी आयात करता है 2030 तक दोनों देशों के बीच में 500 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है, 2024 में दोनों देशों के बीच 129 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ हुआ था, अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ 48 बिलियन डॉलर था। ऊर्जा सुरक्षा दोनों

देशों के आर्थिक संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 2023 में भारत में अमेरिकी निवेश का मूल्य लगभग 50 बिलियन डॉलर था। अमेरिका पर भारत का 216 बिलियन डॉलर का कर्ज है जो अमेरिकी ट्रेजरी बांड में भारत के निवेश के रूप में है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों में वातां के कई दौर हो चुके हैं किंतु अभी तक समझौता नहीं हो पाया है।

अमेरिका ने जिन देशों को 1 अगस्त तक समझौता करने का अल्टीमेटम दिया है उसमें भारत नहीं है। अभी तक दोनों ओर से सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। कृषि और डेयरी पदार्थरे के लिए विशेष रूप से अमेरिका भारत का बाजार अपने लिए टैरिफ मुक्त चाहता है जिसके लिए भारत तैयार नहीं है क्योंकि इन पर करोड़ों लोगों का जीवन-यापन निर्भर है। भारत को अमेरिका सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में गिनता है, भारत से निर्यात होने वाली कई वस्तुओं पर उसने टैरिफ कम करने की मांग रखी है। डिजिटल ट्रेड, सेवाओं, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और कयी औद्योगिक पदार्थरे के भारत से निर्यात पर टैरिफ में कमी के संकेत भारत की ओर से दिए जा चुके हैं। पहली अगस्त तक पूरे समझौते की संभावना कम है किंतु अंतरिम समझौता हो सकता है।
(लेख में विचार निजी हैं)

एंटी-एजिंग दवाओं-सेवाओं के कारोबार

अमित बैजनाथ गर्ग

हाल में मॉडल-अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की कार्डियक अरेस्ट के चलते 42 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। उनके कार्डियक अरेस्ट आने की वजह एंटी-एजिंग दवाओं का सेवन भी बताई जा रही है।

शेफाली सात-आठ सालों से ये दवाएं ले रही थीं। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन उनका व्रत था। वह खाली पेट भी इन दवाओं को ले रही थीं। असल में पिछले कुछ सालों में लोगों में उम्र को छिपाने और जवान दिखने का चलन तेजी से बढ़ा है। इसके लिए वे जम कर पैसा बहा रहे हैं।

अगर एंटी-एजिंग दवाओं-सेवाओं के कारोबार की बात की जाए तो यह देश में तेजी से बढ़ रहा है। इसमें कॉस्मेटिक यानी सर्जरी एवं फिलर्स ट्रीटमेंट और दवाइयां, दोनों शामिल हैं। यह बाजार त्वचा की देखभाल, झुर्रियां हटाने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने वाली दवाओं और उत्पादों की बढ़ती मांग से प्रेरित है। एक अनुमान के मुताबिक, 2023 में देश में एंटी-एजिंग दवाओं-सेवाओं का कारोबार करीब 3,500 करोड़ रुपये का था। 2024 में इसका आकार 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। 2035 तक इसके 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है। यह कारोबार 7-8 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहा है।

कुछ कंपनियों का दावा है कि यह कारोबार दस साल बाद दस हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एंटी-एजिंग दवाओं-सेवाओं का कारोबार कितनी तेजी से पैर पसार रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि लोगों में जवां दिखने की चाहत तेजी से बढ़ रही है। इनमें 30-50 साल तक की उम्र वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। देश में एंटी-एजिंग उपचार के लिए कई तरह की दवाएं, इंजेक्शन तथा सर्जरी बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। इस बिजनेस में दखल रखने वाली कई कंपनियों ने अलग-अलग शहरों में अपने क्लिनिक खोल लिए हैं। मार्केट एक्सपर्ट बताते हैं कि एंटी-एजिंग दवाओं-सेवाओं के मौजूदा कारोबार में अंग्रेजी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां, स्किन संबंधी कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स, बोटोक्स सर्जरी तथा फिलर्स ट्रीटमेंट के बिजनेस शामिल हैं।

एंटी-एजिंग उपचार वह प्रक्रिया है, जिसमें आपको बढ़ती उम्र में भी जवान दिखाया जाता है। यह त्वचा पर झुर्रियां बढ़ने से रोकने का उपचार है। इसके तहत कॉस्मेटिक, दवाइयां, सर्जरी, इंजेक्शन और कोलेजन सप्लीमेंट्स आते हैं। एंटी-एजिंग उपचार अंग्रेजी के साथ आयुर्वेदिक तरीके से भी करने का दावा किया जाता है। अंग्रेजी कंपनियों के साथ कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कंपनियों ने भी दवाएं, ब्यूटी प्रॉडक्ट्स और कोलेजन सप्लीमेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आयुर्वेदिक-होम्योपैथिक कंपनियों की भी अंग्रेजी दवा कंपनियों की तरह इस बाजार पर पूरी नजर है। हालिया कई सर्वे और रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया की तरह भारत में भी एक बड़ी आबादी सोशल मीडिया पर विज्ञापन देख कर प्रॉडक्ट्स का जम कर उपयोग कर रही है। कई सेलेब्रिटी हैं, जो टीवी और सोशल मीडिया पर इस तरह की दवाओं का प्रचार कर रहे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि एंटी-एजिंग की कुछ दवाओं में हार्मोन, स्टेरॉयड या अन्य केमिकल्स होते हैं, जो शरीर के नेचुरल सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं। इससे हार्ट और लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। हार्मोन बैलेंस भी बिगड़ सकता है। इन दवाओं का लगातार सेवन करना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से जुड़ी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। कई लोगों की रिकन बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, कुछ को एलर्जी की समस्या भी होती है।

अयोध्या से तीजा मनाने, इस वर्ष भी अपनी मायके चंदखुरी आयेगी माता कौशल्या

श्री नवनिर्माण गणेश उत्सव समिति राठौर चौक का यह 57 वा साल

लोकशक्ति

गत दो वर्षों से माता कौशल्या के मायके में उनकी मूर्ति स्थापित कर तीजा मनाने के लिए आरंभ की गई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी चित्रोत्पला लोककला परिषद द्वारा,माता कौशल्या संग तीजा तिहार,, पर्व चंदखुरी में मनाने की तैयारी की जा रही है .संस्था के निदेशक राकेश तिवारी के बताया कि इसके लिए आज संस्था के दो वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर एवं राजेश शर्मा याता कौशल्या को तीजा लिवाने अयोध्या खाना हुए।

रवाना होने के पहले दोनों कलाकार परिषद के निदेशक राकेश तिवारी,मार्गदर्शक अशोक तिवारी सहित चंदखुरी जाकर श्रीमती प्रभा यादव से अंगाकर रोटी ग्रहण कर लेवाल पठोने की रस्म पूरा किया . जिसमें श्रीमती यादव द्वारा पुरातन

परम्परा का निर्वाह करते हुए रास्ते में खाने के लिए अंगाकर रोटी,अचार,तथा गुड़ प्रदान किया गया.चंदखुरी से दोनों कलाकार

आज रात अयोध्या के लिए प्रस्थान किए . जहां वे दशरथ भवन से महाराज दशरथ से अनुमति लेकर पूजा पूजा पाठ कर पवित्र मिट्टी

लायेंगे.मूर्ति के लिए लाई गई मिट्टी का दिनांक 4 अगस्त को बाजा गाजा के साथ रेलवे स्टेशन में स्वागत किया जाएगा तथा उसे दिनांक 5

अगस्त को से माता कौशल्या तथा भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार पीलू राम साहू निमोरा को साँपा जाएगा।

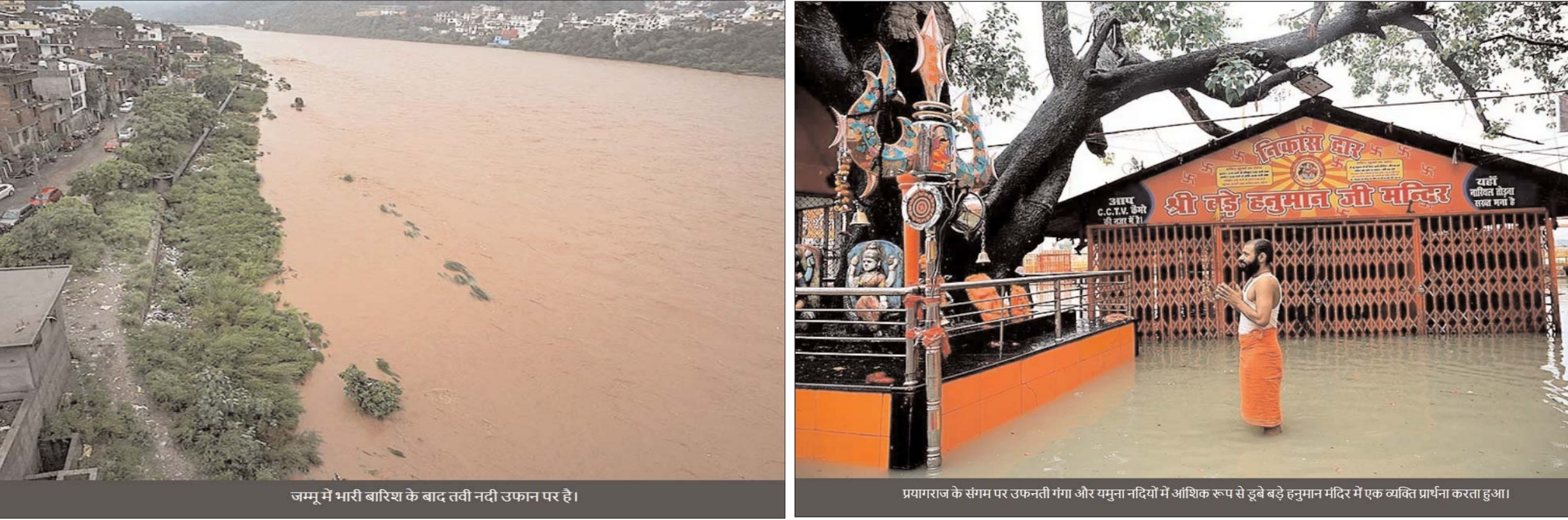
मूर्ति को 22 अगस्त को चंदखुरी ले जाया जाएगा तथा 23 अगस्त को मूर्ति की स्थापना की जाएगी 24 ,25 एवं 26 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रम तथा रस्म का आयोजन किया जाएगा .तथा 27 सितंबर को बासी खिलाने तथा लुगरा भेंट करने के बाद माता की भव्य शोभा यात्रा निकाल कर माता को विदाई दी जावेगी. मिट्टी लाने अथोध्या जाते समय बिदाई देते समय राकेश तिवारी,शोभा यादव,नितेश यादव,एकादशी निषाद, ऋतु निषाद, मधु निषाद, धान बाई, किरण , आरती, सविता, तनु, गिरजा ,कालिया वर्मा, धर्मेश्वरी वर्मा हेमलता यादव सहित अनेक ग्राम वासी उपरिस्थित रहे।

लोकशक्ति

रायपुर की सबसे पुरानी समिती श्री नवनिर्माण गणेश उत्सव समिति राठौर चौक का यह 57 वा साल है इस बार मूर्ति निर्माण का कार्य औंधी गांव जिला दुर्ग के तिलक चक्रधारी को दिया गया है यह मूर्ति मार्च 2025 से बनना चालू हो गई थी मूर्ति की हाइट लगभग 20 फीट और वजन 5000 किलो की रहेगी।

समिति ने आजकल बन रही AI कार्टून मूर्तियां एनीमेशन वाली का विरोध किया और पारंपरिक मूर्ति जो भगवान का असली चेहरा है असली बनावट है जैसा किताबों में बतलाया गया है वैसे ही धाकड़ मूर्ति बैठली जा रही है जिसकी कीमत 1 लाख 60 हजार रुपए है पंडाल का कार्य भी बंगाल के मशहूर बंगाली कार्यकर को

दिया गया है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है और पूरे चौक के सज सजावट में भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है समिति के श्री यश राठौर ने बताया की 4 लाख रुपए कीमत की भगवान शिव शंकर की 3 जीप की झांकी को भी विसर्जन में शामिल किया है।



भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 8 अगस्त 2025 को ‘पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा के विकास’ विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा

पीआईबी
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 8 अगस्त 2025 को उच्च शिक्षा विभाग, नागालैंड के सहयोग से 'पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा का विकास' विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। नागालैंड के राज्यपाल श्री ला. गणेशन ने 8 अगस्त 2025 को कैपिटल कन्वेंशन सेंटर, कोहिमा, नागालैंड में श्री तेम्जेन इम्ना अलोंग, उच्च शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री, नागालैंड और श्री समर नंदा, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय और अभिलेखागार महानिदेशक की उपस्थिति में प्रदर्शनी का उद्घाटन करने की सहमति दी है। यह प्रदर्शनी व्यापक अन्वेषण प्रस्तुत करती है, जो इसकी जनजातीय परंपराओं, भाषाई विविधता, मिशनरी प्रभावों, औपनिवेशिक विरासतों और स्वतंत्रता के बाद के विकास से प्रभावित है। पूर्वोत्तर भारत का शैक्षिक

विकास स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और औपचारिक संस्थानों के गतिशील मिश्रण को दर्शाता है, जिसकी जड़ें मौखिक आदिवासी शिक्षा से लेकर आधुनिक विश्वविद्यालयों तक फैली हैं। यह प्रदर्शनी क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य की वि??शेषता बताती है, जिसमें प्रमुख संस्थानों की स्थापना और समावेशिता एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण नीतिगत पहल शामिल हैं। लोगों के ज्ञान को विकसित करने के लिए, प्रदर्शनी मूल अभिलेखीय दस्तावेजों का उपयोग करते हुए, इस विरासत को विषयगत समूहों के माध्यम से वर्गीकृत करती है। इनमें सरकारी फ़इलें, प्रसिद्ध हस्तियों के निजी कागजात, तस्वीरें, दुर्लभ पांडुलिपियां और राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा नागालैंड राज्य अभिलेखागार में संरक्षित आधिकारिक अभिलेख शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम

पीआईबी
राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी निभाने वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 16,207 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। 01.04.2025 तक, 69,342 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 777 किलोमीटर लंबाई की 12 रेलवे परियोजनाओं (08 नई लाइन और 04 दोहराकरण) को रेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। यह आंशिक और पूरी तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आती हैं, इनमें से 278 किमी चालू हो गई हैं और मार्च 2025 तक 41,676 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 89,436 किलोमीटर के 17,637 सड़क कार्य और 2398 पुलों को मंजूरी दी गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदराज और ग्रामीण गांवों में उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्त पोषण के साथ कई कदम और परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतनेट परियोजना के तहत 6355 ग्राम पंचायतों को सेवा मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3297 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं। नागरिक



उड्डयन मंत्रालय ने देश में बिना सेवा वाले और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने और आम लोगों के लिए यात्रा को सस्ता बनाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना शुरू की थी। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 90 मार्गों का संचालन किया गया है इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) आठ पूर्वोत्तर राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास, संपर्कता, संचार आदि से जुड़ी विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए

वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। यह वित्तीय सहायता एनईएसआईडीएस (सड़कें), एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई), पीएम-डिवाइन, पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की योजनाओं और विशेष विकास पैकेजों (एसडीपी) की पांच केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) को केंद्रीय बजट 2022-23 में 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया था और 12 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल

द्वारा 2022-23 से 2025-26 तक की 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। पीएम-देवाइन योजना का उद्देश्य पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत रूप से वित्तपोषित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास सम्बंधी कमियों को दूर करना है। पर्यटन स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से सम्बंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0)', 'पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएससीआई)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना और 'तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वोत्तर राज्यों सहित, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयासों को पूरा करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दो हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को स्वीकृति दी

पीआईबी**अी।** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए दो हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को आज स्वीकृति दे दी। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 से प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 तक दो हजार करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के आधार पर, एनसीडीसी चार वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगा। एनसीडीसी इस धनराशि का उपयोग सहकारी समितियों को नई परियोजनाएं स्थापित करने/संयंत्रों के विस्तार हेतु ऋण देने और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा। **वित्तीय निहितार्थः** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-एनसीडीसी को दो हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 तक प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये) का अनुदान भारत सरकार की बजटीय सहायता से प्राप्त होगा। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 तक दो हजार करोड़ रुपये के

सहायता अनुदान के आधार पर, एनसीडीसी चार वर्षों की अवधि में खुले बाजार से बीस हजार करोड़ रुपये जुटा सकेगा। **लाभः** इससे देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और शीतगृह जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियां और श्रमिक और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लगभग 2 करोड़ 90 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे। **कार्यान्वयन नीति और लक्ष्यः** (इ) इस योजना का निष्पादन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम करेगा जो परियोजना धनराशि के वितरण, अनुवर्ती कार्रवाई, परियोजना निगरानी और निधि से वितरित ऋण की वसूली करेगा। (ii) दिशानिर्देशों के अनुसार, एनसीडीसी सहकारी समितियों को राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे ऋण प्रदान करेगा। एनसीडीसी के प्रत्यक्ष वित्तपोषण दिशानिर्देशों के मानदंडों को पूरा करने वाली सहकारी समितियों को स्वीकार्य राशि या राज्य सरकार की गारंटी पर सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

(iii) एनसीडीसी, सहकारी समितियों को ऋण, विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजना सुविधाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन/विस्तार के लिए दीर्घकालिक ऋण और उनके व्यवसायों को कुशलतापूर्वक तथा लाभप्रद रूप से चलाने के लिए कार्यशील पूंजी देगा। **रोजगार सृजन क्षमता और प्रभावः** i. इन सहकारी समितियों को दी गई धनराशि से आय उत्पन्न करने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित होंगी और सहकारी समितियों को आवश्यक कार्यशील पूंजी तरलता प्राप्त होगी। ii. आर्थिक लाभों के अलावा, लोकतंत्र, समानता और सामुदायिक सरोकारों के अपने सिद्धांतों के माध्यम से सहकारी समितियां सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के आवश्यक साधन हैं। iii. ऋणों की उपलब्धता, सहकारी समितियों को अपनी क्षमता बढ़ाने, आधुनिकीकरण, विविध गतिविधियां संचालन, उत्पादकता और लाभ बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे कृषक सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।



i। इसके अतिरिक्त, आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सार्वधिक ऋण, विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में रोजगार के व्यापक अवसर भी उत्पन्न करेगा। **पृष्ठभूमिः** सहकारिता क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक उत्थान, आधारभूत ढांचे विकसित करने और रोजगार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में उत्पादन के सभी क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सहकारी समितियां ऋण और बैंकिंग, उर्वरक, चीनी, डेयरी, विपणन, उपभोक्ता वस्तुएं, हथकरघा, हस्तशिल्प,

मत्स्य पालन, आवास इत्यादि में विविध गतिविधियों में संचालित हैं। देश में 8 लाख 25 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनमें 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। देश में 94 प्रतिशत किसान किसी न किसी रूप में सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक योगदान के कारण, डेयरी, मुर्गीपालन एवं पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण एवं शीतगृह, श्रम सहकारी समितियों और महिला सहकारी समितियों आदि क्षेत्रों को दीर्घकालिक और कार्यशील पूंजी ऋण सहयोग आवश्यक है।

पन्द्रह सौ चौवन विसे, कालिन्दी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो सरीर –राजेश्री महन्त

हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया तुलसी जयंती का पर्व शिवरीनारायण मठ में

जांजगीर चांपा /

धर्म एवं आध्यात्म की पावन धरा शिवरीनारायण मठ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक धूमधाम के साथ मनायी गयी। इस अवसर पर दूर-दूर के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से आए हुए मानस के वक्ताओं ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्री रामचरितमानस की कथा लोगों को सुनाया। महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज, कसडोल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण मिश्रा एवं आयोजक निरंजन लाल अग्रवाल जी की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इस अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए राजेश्री महन्त जी महाराज ने कहा कि- *पन्द्रह सौ चौवन विसे,कालिन्दी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो सरीर।। अर्थात तुलसीदास जी महाराज का जन्म संवत् 1554 में जमुना जी के किनारे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के



सप्तमी को हुआ था। उन्होंने कहा कि तुलसी जयंती के अवसर पर हमें न केवल मानस के वक्ताओं एवं श्रोताओं को बल्कि तुलसी दास जी की ही तरह भगवान के चरित्र को जन-जन तक पहुंचने वाले पत्रकार बंधुओ को भी सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हम सभी के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है।*

पूर्व विधायक मिश्रा जी ने कहा कि -धर्म न अर्थ न काम रूचि गति न चहै। निरबान। जनम जनम रति राम पद

यह बरदान न आन ।। मानस मर्मज्ञ दिनेश गोस्वामी ने कहा कि- अस्थि चर्म मय देह मम् ता ऐसी प्रीत।। *मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव ने भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि -साहित्य जगत में तुलसीदास जी महाराज का अतुलनीय स्थान है, इसलिए साहित्यकारों ने लिखा है कि- *सूर -सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास। अब के कवि खाद्योत सम, जहं-तहं करत प्रकाश।।* श्रद्धाओं को मानस मर्मज्ञ राजेंद्र शर्मा, गंगाराम



केवट,भगत राम साहू, गंगाराम पटेल, बिहारी लाल भारद्वाज, सीताराम डडसना, के के शुक्ला, सहित अनेक मानस वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय जांजगीर एवं शिवरीनारायण नगर तथा आसपास के क्षेत्रों से आए हुए पत्रकार बंधुओं तथा मानस वक्ताओं, श्रोताओं को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित पत्रकारों में उपेंद्र तिवारी, पवन चतुर्वेदी, राजकुमार साहू, मनोज थवाईत, मुकेश बैस, प्रशांत सिंह, हेमंत

पटेल, डायमंड शुक्ला, राजेश छत्री, कुणाल गुप्ता, विनोद केसरवानी, मुकेश तिवारी, सीताराम राठौर, दुर्गेश साहू, सुरेश साहू, संतोष अग्रवाल, मनमोहन सिंह कंवर, विजय भूषण सोनी, देवांगन जी के नाम उल्लेखनीय हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्तियार सुखराम दास जी, त्यागी जी महाराज, पुरेंद्र सोनी सहित मठ मंदिर प्रशासन के अनेक अधिकारियों कर्मचारियों ने सराहनीय योगदान दिया। संचालन राधेलाल जायसवाल ने किया।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को 500 करोड़ की स्वीकृति घनश्याम तिवारी ने जताया प्रधानमंत्री एवं सहकारिता मंत्री का आभार



लोकशक्ति। सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जानकारी दी कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU) के अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की एकमुश्त पूंजी अनुदान कोष के रूप में स्वीकृति दी है। यह राशि विश्वविद्यालय में नए भवनों, शोध केंद्रों, छात्रावासों तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी। इस परियोजना को अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत गुजरात के आणंद में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI) की 125 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर विकसित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह भूमि गुजरात सरकार द्वारा 50 वर्षों के लीज पर नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय ने अभी तक तीन शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं और आगामी वर्षों में 50 नए डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है।

विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, व्यवहारिक अनुसंधान और परामर्श सेवाओं के जरिए केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा सहकारी समितियों को दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, नवाचार को बल मिलेगा तथा तकनीकी शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

इस ऐतिहासिक घोषणा पर घनश्याम तिवारी, प्रदेश संयोजक पैकस प्रकोष्ठ, सहकार भारती छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तिवारी ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय प्रशिक्षित युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करेगा, जो देश के कोने-कोने में सहकारी समितियों को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाएगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह विश्वविद्यालय सहकारिता आंदोलन को मजबूती देगा, किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़कर गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

बटनदार चाकू के साथ तीन युवकों को किया गिरफ्तार

लोकशक्ति

जांजगीर चांपा /

बटनदार चाकू के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस ने पूर्व में थाना प्रभारी की मीटिंग लेकर आगामी त्यौहार के महेनजर क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे । इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जेपी गुप्ता के नेतृत्व में थाना चांपा से टीम थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग हेतु रवाना किया गया था । इस दौरान पेट्रोलिंग पुलिस टीम ने



मुखबीर सूचना पर अलग -अलग स्थान से तीन आरोपी संजु केवट, सत्री कंवर एवं सागर कंवर निवासी कंवरपारा को पकड़ा जिसके कब्जे से अलग अलग 3 नग बटनदार

चाकू जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक बाबूलाल दिवाकर,

ज्ञान प्रकाश खाखा, प्रधान आरक्षक उदय सिंह पाटले, आरक्षक शंकर राजपूत, आकाश कालोसिया, मुद्रिका दुबे, संजय साहू, वीरेश सिंह का विशेष योगदान रहा

शासकीय उचित मूल्य दुकान से 42 लाख रुपया का चावल, नमक तथा अन्य खाद सामाग्री का गबन, एक महिला सहित तीन आरोपीयों को किया गिरफ्तार

जांजगीर चांपा / शासकीय उचित मूल्य दुकान से लाखों रुपए की खाद्य सामग्री गबन के मामले में एक महिला सहित तीन आरोपीयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विकास खण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत शासकीय उचित मुल्य दुकान बिरा रोड चाम्पा जिसका संचालन पूर्वा महिला स्व सहायता समूह चांपा की अध्यक्ष गंगाबाई खांडेकर व विक्रेता रितेश खांडेकर, शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटाडबरी चांपा का संचालन पूर्वा महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष गंगाबाई खांडेकर व विक्रेता रामेश्वर खांडेकर उर्फराहुल के द्वारा किया जा रहा था दोनों शासकीय मूल्य उचित दुकान की अध्यक्ष गंगाबाई खांडेकर एवं विक्रेता रामेश्वर खांडेकर एवं रितेश खांडेकर के द्वारा दोनों दुकानों से चावल, नमक व अन्य खाद्य सामग्रियों में हेरफेर तथा गबन कर कुल 42 लाख से ज्यादा रुपये का धोखाधड़ी किया गया है जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 4.मई 2025 को आरोपीयों के विरुद्ध थाना चाम्पा में अपराध धारा पंजीबद्ध कर



विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए *पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस द्वारा आरोपीयों को उनके सकुन्त से पकड़ा गया जिनको धोखाधड़ी करने के सबंध में पूछताछ करने पर प्रारंभिक तौर पर गुमराह करते रहे परंतु बारकी से पूछताछ करने पर सभी ने मिलकर शासकीय उचित मूल्य

की दुकान से खाद्य सामग्री में हेराफेरी कर धोखाधड़ी करने का जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चाम्पा निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, उपनिरीक्षक उमेंद्र मिश्रा, बेलसज्जर लंकड़ा, आरक्षक मुद्रिका दुबे, शंकर राजपूत, आकाश कलोसिया, संजय साहू, वीरेश सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

जवाहर नवोदय चयन परीक्षा– 2026 : कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि, आवेदन अब 13 अगस्त तक आमंत्रित

जांजगीर-चांपा जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय चयन परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वृद्धि की गई है। आवेदन 13 अगस्त 2025 तक आमंत्रित किया गया है एवं चयन परीक्षा 13 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित की जायेगी। प्राचार्य पीएमश्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, चिन्दा ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिले के किसी सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा-5वीं में 31 जुलाई 2025 से पूर्व तक प्रवेश लेकर अध्ययनरत रहेंगे तथा जिनकी जनमतिथि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच है, वे नवोदय विद्यालय समिति के वेबसाइट <https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Inde&/Registration> पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में जनभागीदारी से बनेगी जिले की रैंकिंग एसएसजी 2025 मोबाइल ऐप के माध्यम से दे सकते हैं फीडबैक

जांजगीर-चांपा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का आयोजन भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण 25 जून से 14 अगस्त 2025 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों की स्वच्छता व्यवस्था का आकलन कर उन्हें रैंकिंग देना है। जिले और राज्य की रैंकिंग इसी के आधार पर तय की जाएगी। ग्राम पंचायतों में ग्रामीण एसएसजी 2025 मोबाइल ऐप के माध्यम से दे सकते हैं अपना फीडबैक दे सकते हैं। सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा चयनित स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण से सफलता जनभागीदारी पर निर्भर है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। एसएसजी 2025 मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण नागरिक अपने गांव की सफाई, शौचालय की स्थिति, कचरा प्रबंधन, और सामुदायिक स्थलों की स्वच्छता पर सीधे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो



सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गोकुल गुवाटे ने जिलेवासियों से विशेष रूप से अपील की है कि वे एसएसजी 2025 ऐप पर अधिक से अधिक अभिमत देकर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने में योगदान दें। जांजगीर-चांपा जिला देशभर में स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त करे। इसके लिए आवश्यक है कि हर नागरिक स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी निभाकर वह शौचालय का नियमित उपयोग हो, कचरा न फैलाएं, सामुदायिक स्थलों की सफाई, या फिर एसएसजी 2025 ऐप पर अपनी राय दे सकते हैं।

नगर महिला कांग्रेस की बैठक संपन्न



जांजगीर चांपा / महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती सीमा शर्मा के निर्देश पर आज वाई नंबर 21 के अंबेडकर सामुदायिक भवन में नगर अध्यक्ष महिला श्रीमती शशिकांत हंसेलिया ने बैठक आयोजित की ।आज की बैठक में जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को संगठित होकर कांग्रेस के पक्ष पर कार्य करने पर जोर दिया एवं

आगामी दिनों में हर वाई में बैठक आयोजित किया जाएगा ताकि महिला संगठन का विस्तार हो सके । जिला उपाध्यक्ष वर्षा सिंह ने कांग्रेस की रीति-नीति पर प्रकाश डाला ।महिला नगर अध्यक्ष शशिकांत हंसेलिया ने कहा कि मेरे को जो दायित्व दिया गया है उसे मैं निष्ठा के साथ पूरा करूंगी । इस कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास भी महिलाओं को संगठित

होने हेतु कहा । बैठक में जिला उपाध्यक्ष वर्षा सिंह , रेखा लदेर वाई , नंबर 2 की पार्षद जागेश्वरी सूर्यवंशी , परमेश्वर निर्मले , छाया पार्षद जय कुमार , संध्या निर्मलकर , दीपशिखा हंसेलिया, संतोषी साहू , दुर्गेश्वरी यादव , छाया राठौर , अनीता ठाकुर , प्रेम यादव , राजकुमारी श्रीवास , रोशनी , मुन्नी ,दुर्गा यादव , शशि राठौर एवं अन्य महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित थी ।



जांजगीर-चांपा

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. ए. एल. सिंह ने बताया कि कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में घुमन्तु पशुओं की सुरक्षा के तारतम्य मे जिले के सभी प्रमुख राजमार्गों मे विभाग द्वारा रेडियम रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाकर टैगिंग किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर इनके बैठने या आने से रात में वाहन चालको को दूर से पशुओं के होने का आभास हो सके तथा पशुओं व आम नागरिकों को दुर्घटना की संभावनाओं से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि अब तक 183 पशुओं मे रेडियम रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाया जा चुका है तथा 2385 पशुओं मे टैगिंग किया जा चुका है एवं उक्त कार्य निरंतर जारी है। साथ ही घुमंतू पशुओं मे एफएमडी, गलघोट्ट एवं एकटिंगिया रोग के विरुद्ध रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण भी किया जा रहा है।



खास खबर

मोटरसाइकिल चोरी का कथित आरोपी गिरफ्तार

चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद

कोरबा जिले की दीपका थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल चोरी गिरोह के एक कथित आरोपी को गिरफ्तार किया है। कथित आरोपी के कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने उसको न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी किरण कुमार यादव ने 26 जुलाई को थाना दीपका में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दीपका पुलिस ने एक सद्विध को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करता था। पुलिस ने कथित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। दीपका पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और चोरी की मोटर साइकिलें बरामद कीं।

कोरबा में कांग्रेस संगठन सशक्तिकरण की पहल, मंडल व सेक्टर कमेटियों के गठन पर जोर

कोरबा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। कोरबा जिले में भी मंडल कांग्रेस कमेट्री व सेक्टर कांग्रेस कमेट्री के गठन के लिए बनाए गये प्रभारी अपने दू अपने प्रभार क्षेत्र में बैठक लेना शुरू कर दिये हैं । जिला कांग्रेस अध्यक्ष नत्थुलाल यादव ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि दिनांक 29 जुलाई 2025, दिन मंगलवार को संध्या 3 बजे, बालको प्रभारी-नारायण कुर्रें, दरी प्रभारी दू मुकेश राठौर, कुसमुण्डा प्रभारी कृपाराम साहू, बैठक लेंगे। बालकों में उत्सव वाटिका में कुसमुण्डा में प्रेमनगर सामुदायिक भवन में दरी के साझा कॉलोनी अग्र मंगल भवन में बैठक लेंगे। बैठक को सफल बनाने दरी ब्लॉक अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी, बालको ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा, कुसमुण्डा ब्लॉक अध्यक्ष बसंत चंद्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समय पर उपस्थित होने आग्रह किया है।

मामूली विवाद पर भाई ने की भाई की हत्या

बिलासपुर, । जिले के कोटा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में हुए मामूली विवाद पर भाई ने भाई के सौने पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 28.07.2025 को थाना कोटा में सूचना प्राप्त हुआ कि भाटापारा ग्राम गनियारी में आरोपी झंगल राम सूर्यवंशी के द्वारा अपने बड़े भाई मंगली राम सूर्यवंशी की शराब के नशे में मामूली वाद विवाद पर ईंट से सीने में वार कर हत्या कर दिया है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नूपुर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन पर थाना कोटा में अपराध धारा 103(1) बी.एन.एस. कायम किया गया है। तथा आरोपी झंगल राम सूर्यवंशी को त्वरित गिरफ्तार किया गया। जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर शराब के नशे में मामूली विवाद पर ईंट से सीने को वार कर हत्या करना कबूल किया है ।

समय पर मिली खाद-बीज से युवा किसान बृजपाल की खेती हुई आसान

कोरबा। कोरबा जिले के दूरस्थ क्षेत्र जटगा पंचायत के आश्रित रवागांव के युवा किसान बृजपाल पोते खेती से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन मेहनत और उम्मीद से वे हर साल खरीफ मौसम में अच्छी फसल लेने की कोशिश करते हैं। खरीफ सीजन शुरू होते ही बृजपाल अपनी पत्नी के साथ खेतों में मेहनत करने लगते हैं, जिससे फसल अच्छी हो और परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बने। पहले की तरह इस बार भी उन्होंने खेती की तैयारी शुरू की, उन्हें सहकारी समिति जटगा से समय पर उन्नत किस्म के बीज और खाद (यूरिया, डीएपी) मिल गए। इससे खेती का काम सही समय पर शुरू हो गया और आसानी भी हुई। उन्होंने बताया कि खाद बीज लेने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, ना ही समितियों के अनावश्यक चक्कर लगाना पड़ा। समिति में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता थी। बृजपाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर हर दिन खेत में काम करते हैं। दोनों मिलकर फसल की देखरेख कर रहे हैं। आज बृजपाल अपने खेत मे लगाए धान की फसल में डीएपी और यूरिया का छिड़काव किए है। जिससे फसलों का उत्पादन अच्छ



हो। बृजपाल कहते हैं खाद-बीज समय पर मिलने से खेती करने में आसानी हुई है। इस

बार फसल अच्छी लग रही है, उम्मीद है कि अच्छा उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि खेती

ही उनकी कमाई और जीवन का सहारा है। इसलिए वे पूरी मेहनत कर रहे है ताकि इस

साल पैदावार अच्छी हो और परिवार की जरूरतें पूरी की जा सकें।

झालावाड़ स्कूल कांड को याद कर सहमे अभिभावक

कोरबा, सरकारी भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर कोरबा जिले के विभिन्न स्थानों पर समस्या बनी हुई है । इनका परीक्षण करने के साथ आवश्यक सुधार करने पर जोर दिया गया है लेकिन समय पर काम नहीं होने से दुर्घटनाएं हो रही है। इसी कड़ी में झाबर में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 की छत का प्लास्टर भर भर कर गिर पड़ा। अच्छा यह हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र खुला नहीं था। इसलिए बड़ी अनहोनी टल गई। घटना की जानकारी हुई तो लोग सके में आ गए। अनहोनी टलने पर उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित किया। जानकारी के अनुसार आज सुबह 9 बजे के आसपास यह घटना हुई। नगर पालिका क्षेत्र दीपका से अलग हटकर झाबर में यह आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है जो कटघोरा विकासखंड और आईसीडीएस परियोजना में आता है। जानकारी मिली है कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बनी हुई थी और एक दो अवसर पर लोगों ने विभागीय

अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया था। उनसे कहा गया था कि यहां पर सुधार की जरूरत है और इस दिशा में गंभीरता दिखाई जाए। लेकिन लोगों की बातों को काफी हल्के से लिया गया। इस दौरान समय गुजर और बारिश के प्रभाव से स्थिति प्रतिकूल हुई। इस बीच आज सुबह आंगनबाड़ी केंद्र संख्या तीन का प्लास्टर जोर की आवाज के साथ धराशायी हो गया। जब केंद्र खोलने के लिए कार्यकर्ता और सहायिका यहां पहुंची तो उन्होंने इस दृश्य को देखा। कुछ देर में बच्चों के अभिभावकों को भी इसका पता चला। इस दौरान सभी ने मामले को लेकर हैरानी जताई। उन्होंने कुछ दिन पहले ही राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल भवन की छत के जर्मीदोज होने और 9 बच्चों की जिंदगी समाप्त होने का जिक्र किया। उनका कहना था कि आज जो घटना हुई है , उसका स्वरूप छोटा है लेकिन यह चिंता का विषय तो है ही।

जिले में मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस, कलेक्टर ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

बिलासपुर विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज जिला कार्यालय परिसर से कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने दो जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों रथों को शहर के अलग-अलग मार्गों एवं स्थानों जैसे कि नेहरु चौक, जिला चिकित्सालय, सिम्स, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधी चौक, राजकिशोर नगर, बंधवापारा एवं शहर के प्रमुख मार्गों में भ्रमण कराया गया। प्रचार-प्रसार रथ में जन जागरूकता हेतु फ्लैक्स लगाए गए हैं तथा ऑडियो मैसेज चला कर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गढ़वाल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल



अधिकारी, हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम एवं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा, आईडीएसपी उपस्थित थे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम, बिलासपुर के समन्वय से शहर के जोन क्र. 08 के मुख्यालय कोनी एवं मोपका स्थित गाठान में कैम मोड टैस्टिंग शहर के

सफ़ई कर्मियों का किया गया। जिले में 293 मरीजों का हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हुआ, जिसमें 16 मरीज पंजीटिव मिले एवं 263 मरीजों का हेपेटाइटिस सी टेस्ट हुआ, जिसमें सभी मरीज निगेटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों कलेक्टोरेट परिसर,

नेहरु चौक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर एवं नगर निगम भवन (टाउन हॉल) में हेपेटाइटिस की सामान्य जाकारी, लक्षण एवं बचाव के उपायों को प्रदर्शित करता हुए होर्डिंग चप्पा किये गये हैं। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में अधिछाता एवं संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक, स्टाफनर्स, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल में आए मरीजों को हेपेटाइटिस के लक्षण, कारण एवं बचाव की जानकारी दी गयी। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पोस्टर, चित्र एवं रोलोती के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।

डिजिटल कोरबा की ओर बढ़ता हर कदम –तकनीक से जुड़ता हर नागरिक

ग्रामीण क्षेत्रों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से बढ़ी जनसुविधाएं

कोरबा आज डिजिटल क्रांति की लहर न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से अपना प्रभाव जमा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व एवं सुशासन सरकार की दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप जिले के ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, जिससे ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उनके अपने गांव में ही मिलने लगा है। पहले ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी एवं बैंकिंग सेवाओं के लिए शहरों और तहसीलों तक दूर-दूर जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। वहीं, कई बार लंबी दूरी और अनजान प्रक्रियाओं के कारण जरूरी कार्य भी अधूरा रह जाता था। अब अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण अपनी मूलभूत जरूरतों जैसे पीएम किसान योजना की पंजीकरण, ईपीएस ट्रांजैक्शन, फॉर्मर आईडी बनवाना, आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनवाना व त्रुटि सुधार जैसे कार्य आसानी से अपने गांव में ही कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायतों में इन सुविधा केंद्रों के संचालन से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

शिक्षकों का पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न

0 प्रशिक्षण में सभी 07 विकासखंडों के शिक्षकों ने लिया भाग

0 पांच दिनों तक सीखे खेलों की बारीकियाँ

0 कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने शिक्षक प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर किया सम्मानित

रायगढ़, संवाददाता। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में सचिन तेंदुलकर फ़उंडेशन के तत्वावधान में माण देसी ट्रेवल चैपियन द्वारा संचालित पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस विशेष प्रशिक्षण में जिले के सातों विकासखंडों के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं से चयनित कुल 115 शिक्षक प्रतिभागियों ने भाग लिया, प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रभावी हस्तक्षेप करना रहा। प्रतिदिन प्रशिक्षण के सैद्धांतिक सत्र रायगढ़ के सृजन सभा कक्ष में आयोजित हुए, जबकि प्रायोगिक सत्र रायगढ़ स्टेडियम बोझदादर में संपन्न हुए। जहां शिक्षकों को



स्वयं खेल मैदान तैयार करने, खेल तकनीक, व्यायाम, नींद, पोषण और मांसपेशियों की मजबूती से संबंधित गहन जानकारी दी गई। कार्यक्रम की रूपरेखा जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.वी.राव, डीएमसी नरेंद्र चौधरी तथा कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी एवं एपीसी भुवनेश्वर पटेल के नेतृत्व में तैयार की गई। पांच दिवसीय प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य जिसमें एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी, गोला फेक, भाला फेक, लम्बी कूद, ऊंची कूद आदि खेलों की तकनीक का प्रशिक्षण मांसपेशियों को मजबूत करने के व्यायाम, नींद और संतुलित पोषण के प्रति जागरूकता, खेलों के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाना,

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना,स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने की प्रेरणा देना सामान्य जीवन कौशल जैसे संवाद कौशल, आत्म-सम्मान, साहस और व्यक्तित्व विकास को सशक्त बनाना, खेल के इतिहास पर व्याख्यानों के माध्यम से बौद्धिक दृष्टिकोण का विस्तार करना रहा। यह कार्यक्रम न केवल शिक्षकों के स्वास्थ्य और खेल शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में कारगर साबित हुआ, बल्कि इससे वे अपने विद्यालयों में बच्चों को एक जागरूक, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में और अधिक सक्षम बन सकेंगे। माण देशी चैपियन ट्रेवल कोच प्रोग्राम के माध्यम से खेल माध्यम से रायगढ़

जिले में सरकारी स्कूलों की शारीरिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सशक्त पहल की गई है। जिसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और उनके जीवन कौशल पर दिखाई देगा। माण देशी फउंडेशन एवं जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के संयुक्त प्रयास से फउंडेशन के प्रमुख प्रभात सिंह, संस्थापक, ओंकार गुंजारी, निदेशक, प्रवीण फेंगरे, मुख्य कोच, हनुमंत चोरपडे, सीनियर कोच, सनिका, कोच, सुशांत आवले, सहायक कोच, अनुराग शिंदे इतिहासकार एवं अमीन अमरी इंटर्न, इन्हीं विशेषज्ञों द्वारा सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ साल एवं मोमेंटो से सम्मानित करते हुए सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी और नोडल अधिकारी भुवनेश्वर पटेल के नेतृत्व में रायगढ़ डीएसओ जीवनलाल नायक, बीआरसी मनोज अग्रवाल, व्याख्याता बीर सिंह, सीएससी राजकमल पटेल, सुशील चौहान, विकास पटेल, श्रीमति आशा यादव, धर्मेन्द्र कोर्चे, निवास साव, गेंद कुमार पटेल, पीटीआई प्रभुदत्त पाढ़ी, प्रधान पाठक का विशेष योगदान रहा।

विकलांग युवती ने कलेक्टर से लगाई नौकरी की गुहार- दिया आवेदन

कोरबा

जिले के ग्राम गोढी की एक विकलांग युवती तेरसबाई यादव ने कलेक्टर कोरबा को एक आवेदन सौंपकर नौकरी की गुहार लगाई है। युवती तेरस बाई ने बताया कि वह जन्म से ही अपने लेफ्ट पैर से 40 परसेंट विकलांग हैं और गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बीए फह्नल और एमए अंजेली की पढ़ाई करी है, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण आगे की पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। उसने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि उन्हें शिक्षा विभाग या किसी अन्य विभाग में विकलांग कोटा में नौकरी देने की कृपा करें। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने से वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर पाएंगी।

युवती ने आगे बताया कि वह अपने परिवार की पहली महिला हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनना चाहती हैं। कलेक्टर कोरबा ने तेरस बाई के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया है कि उनके मामले को गंभीरता से देखा जाएगा और जल्द ही नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

इंडिपेंडेंस कप कराटे प्रतियोगिता में लेवल अप एमएमए अकादमी की शानदार उपलब्धि

कोरबा, । छत्तीसगढ़ राज्य कराटे फेडरेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय इंडिपेंडेंस कप राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में लेवल अप एमएमए अकादमी, कोरबा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते। कोरबा जिला कराटे डू स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश बंजारे ने बताया कि यह प्रतियोगिता 26 व 27 जुलाई को स्वामी विवेकानंद इंडोर स्टेडियम, कोटा, रायपुर में संपन्न हुई।इसमें विजेता खिलाड़ी अब 08 से 10 अगस्त को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम को

भी देखा और खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने प्रेरणा दी। जिला अध्यक्ष अविनाश बंजारे में बताया कि जिले के बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक प्राप्त किए हैं इसमें स्वर्ण पदक विजेता अश्वत पांडेय, जैस्मिन कुर्रें, मिथा अल्फ्रट, आयुष उरांव, धीरज बरेठ, अनीश खरे, अमन टोप्पो, रजत पदक विजेता में गुंजन देवांगन, अर्धत नारायण पांडेय, पारस बंजारे, एकदा महन्त, स्वाति ओगरे, नेवान आर. पिब्लै, अनुज अग्रवाल, आशुतोष पाठक, प्रतीक सिंह, आर्या सेठी, कांश्य पदक विजेता अश्वत साहू, लोमश प्रसाद सिन्हा, काव्या श्रीवास, महेव एक्क, आर्यन विकटर सिंह, रुचि श्री राहंगडाले, संपदा सक्सेना, दीपक रोहदास,समीर कंवर, रागिनी निर्मलकर,लखन साहू,एजेल यादव काता कैटगरी, संपदा सक्सेना ने रजत पदक प्राप्त किया।

सीएम विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित 17, छग्न सदन में राज्य के सांसदों से सौजन्य भेंट की

रायपुर। इस अवसर पर आयोजित रात्रि भोज के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता से राज्य के हित और जमीनी जरूरतें राष्ट्रीय प्लत्फॉर्म पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत हो पाती हैं। इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों की चर्चा भी हुई। सांसदों ने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर फीडबैक साझा किया और राज्य के जमीनी अनुभवों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, निवेश आकर्षण, युवाओं को मिल रहे नए अवसर, किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनकारी विकास कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी।



अवैध शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार, 60 पौवा देशी शराब और 8,000 जब्त

मुख्यमंत्री साय ने ऑपरेशन महादेव पर जताया गर्व, सुरक्षाबलों को दी श्रद्धांजलि

रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ऑपरेशन महादेव की सफलता पर गर्व जताते हुए सुरक्षाबलों को सलामी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक भावनात्मक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पहलूगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकियों के खाते पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री साय ने लिखा कि ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलूगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के पराक्रम से तीनों गुनहवार सजा पा चुके हैं। मैं हमारे सुरक्षाबलों के शौर्य को

नमन करता हूँ। यह ऑपरेशन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के संकल्प का सशक्त परिणाम है। यह आतंक के विरुद्ध भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया है। यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है उन तमाम दुश्मनों को जो भारत की भूमि पर आतंकी मंसूबे लेकर आते हैं। भारतीय सेना के वीर जवानों का पराक्रम हर देशवासी के हृदय में गर्व और विश्वास भर देता है। मुख्यमंत्री का यह बयान देशभर में हो रहे सुरक्षा बलों के साहसी अभियानों के प्रति जनसमर्थन को दर्शाता है। ऑपरेशन महादेव न केवल एक आतंक रोधी कार्रवाई है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुका है।

जल जीवन मिशन के 9 ठेकेदार के टेंडर निरस्त, कार्यों में लेट-लतीफी को लेकर कलेक्टर चतुर्वेदी ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए



रायपुर। कार्यों में लेट-लतीफी को लेकर कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने कार्य में लापरवाही और धीमी प्रगति पर विभागीय अधिकारियों एवं कार्यरत ठेकेदारों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने 9 ठेकेदारों के टेंडर निरस्त कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए तथा कहा कि जल जीवन मिशन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव, सहायक कलेक्टर श्री अश्वय डोसी सहित जिले के समस्त एसडीओ, सब इंजीनियर्स एवं ठेकेदार उपस्थित थे। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि मिशन मोड में संचालित इस योजना के तहत सभी ठेकेदार अपने कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें। प्रत्येक माह कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी तथा भौतिक सत्यापन के आधार पर वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। जहां कार्य अपूर्ण या धीमी गति से पाए जाएंगे, वहां अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने कार्य अधूरा छोड़ दिया है या जिनकी प्रगति अत्यंत धीमी है, उनके टेंडर तत्काल निरस्त कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए।

समीक्षा बैठक में 9 ठेकेदारों के विरुद्ध टेंडर निरस्तीकरण एवं ब्लैकलिस्टेड के निर्देश दिए गए, जिनमें मे. गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, मे. जितेश्वर साहू, मे. अजय सेल्स, मे. मुकुल मंत्र कंस्ट्रक्शन, मे. आशीष ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन, रायगढ़, श्री दुर्गाश चंद्रा, मे. हरिकृष्णा कंस्ट्रक्शन, मे. हीरादेवी, जांजगीर-चांपा, मे. के.पी. राठौर, जांजगीर-चांपा शामिल हैं। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन्हें तत्काल हैंडओवर किया जाए। उन्होंने कहा कि सीईओ जनपद एवं विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा स्थलों का भौतिक सत्यापन कर, निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य पूर्ण पाए जाने पर पंचायतों को हैंडओवर की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित की जाए। बैठक में फेल्ट में आ रही समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कुछ स्थलों पर जल स्रोत की अनुपलब्धता के मद्देनजर कलेक्टर ने विभाग को बोर खनन के माध्यम से जल स्रोत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सोलर विलेज योजनाओं में क्रेड द्वारा किए जाने वाले कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर फंक्शनल नल कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि एक ही स्थान पर सिंगल और मल्टी विलेज स्कीम के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए दो बार खुदाई की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए दोनों योजनाओं के ठेकेदार समन्वय कर एक बार में कार्य पूर्ण करें।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की बैठक सम्पन्न

रायपुर। ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण-बंटवारे का अधिकार, ग्रामीणों को तहसील कार्यालयों के चक्र से मिलेगी मुक्ति-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक हुई। बैठक में चर्चा की शुरुआत पंचायतों के माध्यम से अविवादित नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया से हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में अविवादित राजस्व मामलों का भी समाधान कर रही हैं, जिससे ग्रामीणों को तहसील के चक्र नहीं लगाने पड़ेंगे और शासन-प्रशासन के बीच की दूरी कम होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों में इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत



विभाग श्रीमति निहारिका बारीक सिंह, सचिव श्री भीम सिंह, संयुक्त सचिव श्री धर्मेश कुमार साहू के अलावा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए बनाए गए 'ग्राम संपदा ऐप' की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों में उपलब्ध परिसंपत्तियों की पारदर्शिता के लिए ऐप को अपडेट किया जाए और

इसकी तकनीकी समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाए। सभी जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक संशोधन किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में 'अटल डिजिटल सुविधा केंद्र' की कार्यप्रणाली पर भी विशेष चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन की सुविधा सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने

यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में ही नकद निकासी की सुविधा होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को दूरस्थ बैंकों के चक्र न लगाने पड़ें। शेष बचे पंचायतों में भी जल्द ही यह केंद्र खोला जाएगा। बैठक में आगामी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ कर्मवीर पंचायत जनप्रतिनिधि पुरस्कार की शुरुआत किए जाने पर चर्चा की और दिशा-निर्देश एवं मापदंड तय करने के निर्देश दिए।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पूर्व एवं पश्चात् प्रदेश में आकर बसे परिवारों की पृथक पंजी व्यवस्था, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे विषयों पर भी गंभीर मंथन हुआ। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमर छत्तीसगढ़ योजना की शुरुआत बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों को राजधानी रायपुर बुलाकर दो से तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क्रेडा चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी पर वेंडर्स ने लगाया कमीशन मांगने का आरोप



रायपुर । क्रेडा के वेंडर्स ने क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी पर कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखित शिकायत दी है। वेंडर्स ने सवन्नी पर 3 प्रतिशत कमीशन की मांगने तथा नहीं देने पर कार्यों की जांच कराने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वेंडर्स ने शिकायत में बताया कि वे क्रेडा में विगत कई सालों से वेंडर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी के द्वारा उनके निजी सहायक वैभव दुबे के माध्यम से 3 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है और नहीं देने पर कार्यों की जांच कराने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा रही है। सचिवालय ने शिकायत को गंभीरता से लिया है और ऊर्जा सचिव से रिपोर्ट मांगी है। इधर क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी ने अपने खिलाफ शिकायत को आधारहीन और फर्जी करार दिया है।

कृषि और आदिवासी विकास को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस में तीन जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली

कृषि और आदिवासी विकास को लेकर मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस में तीन जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली

रायपुर। किसानों को जैविक खेती, कोदो-कुटकी और उन्नत कृषि के लिए जागरूक करें: कृषि मंत्री श्री नेताम प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज जिला कार्यालय कांकेर के सभागार में कांकेर, बालोद और धमतरी जिलों के कृषि एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, खाद-बीज वितरण एवं किसानों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा भी मौजूद थे। कृषि मंत्री श्री नेताम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को जैविक खेती, कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक एवं लाभकारी फसलों के लिए प्रेरित करें तथा उन्नत कृषि तकनीक के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि खाद एवं बीज का समय पर



वितरण सुनिश्चित करते हुए योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से अंतिम छोर के किसान तक पहुंचे, यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मृदा की सेहत को संरक्षित रखने हेतु रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और जैविक खादों के उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया। उद्यानिकी के क्षेत्र में मुन्गा, ऑयल पाम, मसाला फसलें और कोदो-कुटकी जैसी फसलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भी उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में संचालक कृषि एवं प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम श्री अजय कुमार अग्रवाल द्वारा तीनों जिलों में बीज एवं खाद की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की

स्थिति की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कांकेर जिले में 38,869.35 क्विंटल धान बीज में से 34,756.60 क्विंटल का वितरण हो चुका है। यूरिया खाद 25,568.13 मीट्रिक टन में से 20,525.87 मीट्रिक टन वितरित किया गया है। डीएपी खाद 7,024.15 मीट्रिक टन में से 6,002.05 मीट्रिक टन तथा एनपीके 9,129.55 मीट्रिक टन में से 7,216.73 मीट्रिक टन वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कांकेर जिले के 75,559 कृषक बीमित हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में 17,575 कृषकों का बीमा किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिले के 82,395 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

गांव-गांव लगाए जा रहे आयुर्वेद शिविर 327 मरीजों को मिला अब तक निःशुल्क उपचार



रायपुर। आयुर्वेद चिकित्सा विभाग द्वारा गांव-गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया जा रहा है और जरूरतमंद ग्रामीणों का निःशुल्क उपचार कर आयुर्वेदिक दवाइयों वितरित की जा रही है। रोगियों को उचित परामर्श और परहेज संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। पत्र में एसोसिएशन ने यह भी बताया कि इस शिकायत में न तो किसी व्यक्ति का नाम, पता, या संपर्क जानकारी दी गई है, जो इसे एक गंभीर और वास्तविक आरोप के रूप में स्थापित करने में नाकाम साबित होती है। संगठन का मानना है कि यह किसी शरारती व्यक्ति की ओर से की गई सुनियोजित कोशिश हो सकती है। इसके अलावा, एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि ऐसी गुमनाम और अप्रमाणित शिकायतों को गंभीरता से न लिया जाए और उन्हें सख्ती से निपटा जाए। उनका कहना है कि इस प्रकार की शिकायतों को रिकॉर्ड में डालकर अधिकारी और संस्थाएं अपनी ईमानदारी से काम करती रहेंगी, जिससे उनका मनोबल ऊँचा बना रहेगा। इससे पहले क्रेडा के कुछ वेंडरों, जिनमें सुरेश कुमार प्रमुख थे, ने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने उनके निजी सहायक वैभव दुबे के माध्यम से पुराने कार्यों के लिए तीन प्रतिशत का कमीशन मांगा। आरोपों में यह भी कहा गया था कि यदि वेंडर इस राशि को नहीं देंगे तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा रही है। इन आरोपों से वेंडरों में असंतोष फैलने की खबरें भी आई हैं।

माह में आयोजित शिविरों में कुल 327 मरीजों ने लाभ प्राप्त किया, जिसमें रमभाटा से 41, जिलाडी से 34, बारडोली से 94, बोदा से 61 तथा चनघोरी से 97 रोगी शामिल हैं। इन शिविरों में मरीजों को आयुर्वेदिक दवाई, शास्त्रोक्त एवं अन्य पेटेंट औषधियां वितरित किया गया। बुन्गा केंद्र में प्रत्येक माह जीवनशैली में बदलाव हेतु सत्र, औषधीय पौधों की जानकारी, मितानिन प्रशिक्षण, नियमित योगाभ्यास, एनसीडी स्क्रीनिंग एवं अन्य जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सौंपा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र सौंपा है, जिसमें क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि जनदर्शन में जो शिकायत की गई है, वह पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और बिना किसी प्रमाण के की गई है। पत्र में एसोसिएशन ने यह भी बताया कि इस शिकायत में न तो किसी व्यक्ति का नाम, पता, या संपर्क जानकारी दी गई है, जो इसे एक गंभीर और वास्तविक आरोप के रूप में स्थापित करने में नाकाम साबित होती है। संगठन का मानना है कि यह किसी शरारती व्यक्ति की ओर से की गई सुनियोजित कोशिश हो सकती है। इसके अलावा, एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि ऐसी गुमनाम और अप्रमाणित शिकायतों को गंभीरता से न लिया जाए और उन्हें सख्ती से निपटा जाए। उनका कहना है कि इस प्रकार की शिकायतों को रिकॉर्ड में डालकर अधिकारी और संस्थाएं अपनी ईमानदारी से काम करती रहेंगी, जिससे उनका मनोबल ऊँचा बना रहेगा। इससे पहले क्रेडा के कुछ वेंडरों, जिनमें सुरेश कुमार प्रमुख थे, ने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने उनके निजी सहायक वैभव दुबे के माध्यम से पुराने कार्यों के लिए तीन प्रतिशत का कमीशन मांगा। आरोपों में यह भी कहा गया था कि यदि वेंडर इस राशि को नहीं देंगे तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा रही है। इन आरोपों से वेंडरों में असंतोष फैलने की खबरें भी आई हैं।

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और पूर्व विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह तरीका है कि वह झूठ को बार-बार दोहराकर उसे सच साबित करने की कोशिश करती है।